शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार
मध्यप्रदेश

डेढ़ माह देरी से होंगी यूजी-पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं

तैयारी ● 20 हजार विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे परीक्षाओं में, एक माह में होगा मूल्यांकन

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियां पिछड़ चुकी हैं। हर साल जहां नवंबर-दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षाएं होती थीं, वहीं इस बार सत्र 2020-21 की परीक्षाएं 45 दिन देरी से जनवरी-फरवरी में करवाने की तैयारी है। संक्रमण को देखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा परिणाम 30 दिन में जारी करेंगे।

कोरोना संक्रमण के कारण ही सत्र 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया नवंबर तक चली है। एक दिसंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बीबीए, बीसीए, बीए मास कम्युनिकेशन, एमकॉम, एमएससी, एमए की पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। इसमें लगभग 20 हजार परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है कि सेमेस्टर परीक्षाएं संक्रमण की वजह से पिछड़ रही हैं। करीब 45 दिन परीक्षा आगे बढ़ाई गई है। जनवरी-फरवरी के बीच ओपन बुक पद्धति से परीक्षा होगी। सभी पेपर वेबसाइट पर अपलोड होंगे। जवाब लिखकर विद्यार्थियों को पांच-सात दिन

के बीच कॉपियां जमा करानी होंगी। उन्होंने बताया कि अंतिम वर्ष की तर्ज पर कॉलेजों को संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। यहां से उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्र में आएंगी। फिर इन्हें शिक्षकों को जांचने के लिए देंगे।

स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए पृथक प्रश्नपत्र : डॉ. तिवारी का कहना है कि मूल्यांकन कार्य 30 दिनों में पूरा करना है। उसके आधार पर विद्यार्थियों का परिणाम बनाया जाएगा। वे बताते हैं कि स्वाध्यायी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रश्नपत्र अलग से अपलोड किए जाएंगे।

अक्टूबर से शुरू हुआ सत्र : प्रभारी कुलसचिव अनिल शर्मा का कहना है कि तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020-21 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इनकी परीक्षाएं जनवरी में करवाई जाएंगी। वहीं पहले सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में पेपर अपलोड होंगे। उन्होंने बताया कि 90 दिनों बाद सेमेस्टर परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। उच्च शिक्षा विभाग से सिलेबस कम करने को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।

पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा शुरू

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय की पीएचडी कोर्सवर्क की परीक्षा गुरुवारको ऑनलाइन शुरू हुई। कोरोना 19 के चलते यह परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से ऑनलाइन रखी गई। जिसमें सुबह 11 से 12 बजे तक छात्रों को पेपर अपलोड, 12से 3 बजे तक कॉपी में लिखने और 3 से 4 बजे तक कॉपी मेल के माध्यम से जमा की गई। यह परीक्षा शहर के चार केन्द्रों पर आयोजित हुई। जिसमें करीब 250 शोद्यार्थी शामिल हुए।

एनसीसी भर्ती में 32 छात्रों का चयन

दतिया, ब्यूरो। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ोनी में एनसीसी जूनियर डिवीजन की भर्ती का आयोजन किया गया। 15 एमपी बटालियन कम्पू ग्वालियर से कर्नल अरिंदम मजूमदार, सूबेदार मेजर अलीशेर खान, हवलदार मोहर सिंह ने छात्रों का फिजिकल फिटनेस, मेडीकल फिटनेस, दौड़ एवं 20 बैंड स्ट्रैंच कर परीक्षण किया। पहले राउण्ड की भर्ती में 32 छात्रों का चयन किया गया। भर्ती प्रक्रिया विद्यालय के प्राचार्य एम.एस. मिश्रा एवं केयर टेकर एनसीसी देवेन्द्र सिलारपुरिया के निर्देशन में आयोजित की गई। कर्नल मजूमदार व सूबेदार मेजर खान द्वारा एनसीसी के लाभ के बारे में छात्रों से चर्चा की गई।

विद्यार्थी परिषद ने किया छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

ग्वालियर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा प्रांत सहमंत्री एवं महानगर मंत्री अनमोल व्यास के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजाति छात्रा के साथ किए जा रहे अत्याचार के विरोध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर विरोध-प्रदर्शन किया।

परीक्षाएं

ल्यांकन

र्थियों के लिए प्रश्नपत्र अलग से
ड किए जाएंगे।

क्टूबर से शुरू हुआ सत्र :
कुलसचिव अनिल शर्मा का
है कि तीसरे और पांचवें सेमेस्टर
ार्थियों के लिए सत्र 2020-21
र से शुरू हुआ है। इनकी परीक्षाएं
में करवाई जाएंगी। वहीं पहले
र वाले विद्यार्थियों के लिए फरवरी
ले सप्ताह में पेपर अपलोड होंगे।
बताया कि 90 दिनों बाद सेमेस्टर
एं करवाई जा सकती हैं। उच्च
विभाग से सिलेबस कम करने को
कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।

डीएवीवी और आइसीएसआइ के बीच करार

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नैक से 'ए+' ग्रेड प्राप्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों को कंपनी सेक्रेट्री के क्षेत्र में पारंगत बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आइसीएसआइ) से करार किया है। पांच साल के इस अनुबंध के तहत फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाएगा। संस्थान की तरफ से दीक्षा समारोह में बीकॉम के मेरिट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार को दोनों संस्थानों के बीच औपचारिक अनुबंध हो गया है। आइसीएसआइ की लाइब्रेरी का भी विद्यार्थी इस्तेमाल कर सकेंगे।

अनुबंध का फायदा कॉमर्स और मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को मिलेगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेट्री क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ इन छात्र-छात्राओं को पढ़ाने आएंगे। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट भी वहां जाकर कक्षाएं ले सकेंगे। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सेमिनार, कार्यशाला और कांफ्रेंस के जरिए कंपनी सेक्रेट्री की बारीकियां बताएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर कंपनी सेक्रेट्री के क्षेत्र में नए संशोधन व नियमों के बारे में समझाया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को आइसीएसआइ की लाइब्रेरी में रखी किताबें इस्तेमाल करने की छूट भी रहेगी। विश्वविद्यालय की तरफ से नोडल अधिकारी आइएमएस के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दीपक श्रीवास्तव को बनाया है। गुरुवार को डीएवीवी और आइसीएसआइ के बीच करार हुआ। अनुबंध पर कुलपति डॉ. रेणु जैन और संस्थान के सीए आशीष कुमार ने हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान आइएमएस की डायरेक्टर डॉ. संगीता जैन भी मौजूद थी। प्रभारी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा का कहना है कि बीकॉम कोर्स में मेरिट आने वाले विद्यार्थी को गोल्ड मेडल और बाकी विद्यार्थियों को संस्थान की तरफ से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

अच्छा प्रयास

- **फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए पहल**
- **बीकॉम में मेरिट विद्यार्थियों को संस्था की तरफ से मिलेगा गोल्ड मेडल**

मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहने वाले छह विद्यार्थियों ने नीट में पाई सफलता

मुंबई (एजेंसी)। अपराध तथा ड्रग्स के लिए बदनाम मुंबई के पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र की गोवंडी झुग्गी बस्ती के छह विद्यार्थियों ने तमाम तरह के व्यवधानों से पार पाते हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) में सफलता पाकर दूसरों के लिए एक नजीर पेश की है।

इनमें से एक है जैवा खान। इसके पिता भी डॉक्टर हैं। वह कहती है कि कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी देखकर उसका डॉक्टर बनने का संकल्प और दृढ़ हुआ। इसी तरह एक कैटरर के बेटे सैफ आसिफ जोगले का कहना है कि उसने गरीबों को इलाज के लिए भटकते देखकर तय किया कि डॉक्टर बनना है और यह सपना पूरा होने जा रहा है।

गोवंडी में स्थानीय डॉक्टरों का एक एसोसिएशन बनाने वाले डॉक्टर जाहिद खान कहते हैं कि बदनाम इलाका होने के कारण अधिकतर लोग यहां आना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने अपने बच्चों को ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा हमारा एसोसिएशन एक वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिसमें हम बच्चों के माता-पिता को प्रेरित करते हैं।

वेटरनरी स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाएं अब जनवरी में होंगी

विद्यार्थियों की मांग पर विवि प्रशासन ने लिया निर्णय

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के वेटरनरी विवि जबलपुर से स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को विवि ने मान लिया है। दरअसल, जबलपुर समेत रीवा और महू वेटरनरी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा 20 दिसंबर से कराई जानी थी। इसको लेकर विवि प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन विद्यार्थियों की मांग थी कि विवि प्रशासन ऑनलाइन परीक्षा ले या फिर मुख्य परीक्षा तिथि बढ़ाए।

अब मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर के बजाय जनवरी के पहले सप्ताह के बाद होगी। हालांकि अभी तिथि तय नहीं है, लेकिन संभवत: आठ से 12 जनवरी के बीच तीनों कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी।

विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा कराने की कर रहे मांग

जबलपुर, रीवा और महू के स्नातकोत्तर के छात्र-छात्राएं विवि प्रशासन से कोरोनाकाल को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर विवि का कहना है कि इन छात्रों को शोध कार्य करने के लिए विवि या कॉलेज आना होगा। वहीं इनकी संख्या स्नातक के छात्र-छात्राओं की तुलना में बहुत कम है। स्थिति को देखने के बाद ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है।

अब क्या होगा

विवि के कुलपति प्रो. एसपी तिवारी ने डीन फैकल्टी डॉ. आरपीएस बघेल से लेकर डीआइ डॉ. एसके जोशी और परीक्षा प्रमुख डॉ. दास को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को मानते हुए ऑफलाइन परीक्षा तिथि दिसंबर के बजाय जनवरी में करें। इसके बाद विवि ने तिथि बदलने का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि तीनों कॉलेज के विद्यार्थियों ने डीन को परीक्षा ऑनलाइन कराने के लिए ज्ञापन भी दिया है।

लॉ और नर्सिंग कॉलेजों की फीस इस साल नहीं बढ़ेगी!

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के प्राइवेट लॉ और नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने फीस बढ़ोतरी की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव प्रवेश एवं फीस विनियामक कमेटी को भेजा है। लॉ और नर्सिंग कॉलेजों की मांग है कि फीस में करीब 30 फीसद तक की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसे करीब सौ कॉलेजों की फीस तय करने को लेकर कमेटी ने सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई पूरी होने के बाद उनके आय-व्यय के आधार पर फीस तय की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक कमेटी इस बार लॉ और नर्सिंग कॉलेजों की फीस में इजाफा करने के पक्ष में नहीं है। कॉलेजों के आय-व्यय के आधार पर कमेटी का मानना है कि मौजूदा फीस ही पर्याप्त है। ऐसे में इस साल इन दोनों विषयों की फीस हर साल की तरह रहेगी। वर्तमान में नर्सिंग कॉलेजों की सालाना फीस करीब 50 हजार रुपये से 80 हजार रुपये है। जबकि लॉ कॉलेजों की सालाना फीस करीब 20 हजार से 40 हजार रुपये।

ऐसे तय होती है फीस

कमेटी हर तीन साल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, डेंटल, एमबीए, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन और लॉ कोर्सेस संचालित करने वाले कॉलेजों से फीस तय करने के लिए प्रस्ताव मंगाती है। कॉलेजों को प्रस्ताव ऑनलाइन देना होता है। इसके साथ कॉलेजों को उनके सालभर की आय और व्यय का ब्योरा देना होता है। इस आधार पर कमेटी कॉलेजों की फीस तय करती है।

प्राइवेट कॉलेज संचालकों ने लॉ और नर्सिंग विषय की फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कमेटी को दिया था। कमेटी ने कॉलेजों की ओर से प्रस्ताव के साथ दिए गए आय-व्यय के ब्योरे की पड़ताल की है। इस आधार पर कमेटी ने तय किया है कि इस साल दोनों विषयों की फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

-रवींद्र कान्हेरे, अध्यक्ष एएफआरसी

वेटरनरी स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाएं अब जनवरी में होंगी

विद्यार्थियों की मांग पर विवि प्रशासन ने लिया निर्णय

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के वेटरनरी विवि जबलपुर से स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को विवि ने मान लिया है। दरअसल, जबलपुर समेत रीवा और महू वेटरनरी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा 20 दिसंबर से कराई जानी थी। इसको लेकर विवि प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन विद्यार्थियों की मांग थी कि विवि प्रशासन ऑनलाइन परीक्षा ले या फिर मुख्य परीक्षा तिथि बढ़ाए।

अब मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर के बजाय जनवरी के पहले सप्ताह के बाद होगी। हालांकि अभी तिथि तय नहीं है

अब क्या होगा

विवि के कुलपति प्रो. एसपी तिवारी ने डीन फैकल्टी डॉ. आरपीएस बघेल से लेकर डीआइ डॉ. एसके जोशी और परीक्षा प्रमुख डॉ. दास को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को मानते हुए ऑफलाइन परीक्षा तिथि दिसंबर के बजाय जनवरी में करें। इसके बाद विवि ने तिथि बदलने का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि तीनों कॉलेज के विद्यार्थियों ने डीन को परीक्षा ऑनलाइन कराने के लिए ज्ञापन भी दिया है।

बेरोजगार छात्रों के लिए दिया प्लेसमेंट सेल बनाने का सुझाव

एग्री अंकुरण वेलफेयर एसो. की ऑनलाइन बैठक

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्यप्रदेश के शासकीय कृषि महाविद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत और भूतपूर्व छात्रों की संस्था एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें कॉलेज के वर्तमान और भूतपूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया। भविष्य में संगठन को किस दिशा में काम करना चाहिए, इसे लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

वैठक में मधुमक्खी पालन, एफपीओ, स्वरोजगार सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव सामने आए। इसमें कीटनाशक कंपनी के प्रवंधक दिनेश शर्मा ने सुझाव दिया कि वर्तमान और पूर्व छात्रों के काम के हिसाव से एक डायरेक्टरी वनाएं ताकि सभी एक-दूसरे को जान सकें। पूर्व छात्र प्रमोद गुप्ता ने प्लेसमेंट सेल वनाने का सुझाव दिया, जिससे वर्तमान में वेरोजगार घूम रहे छात्रों को राहत मिलेगी। आत्मा परियोजना के विशाल पाटीदार ने मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण का सुझाव दिया। पूर्व छात्र व वैंक अधिकारी रवि गर्ग ने सुझाव दिया कि अंकुरण की फाइनेंस टीम वननी चाहिए जो कृषि स्नातकों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता करे। कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के पूर्व छात्र व सहायक कृषि निरीक्षक जगदीश कुर्मी, सहायक संचालक कृषि व पूर्व छात्र वसीम खान, सहायक संचालक गोविंद शर्मा और पूर्व छात्र मुकेश जाट ने भी संवोधित किया।

एक्सपोर्ट बिजनेस पर भी मिलेगा मार्गदर्शन

अमेरिकन एनजीओ के अधिकारी व पूर्व छात्र नीरज राठौर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट विजनेस करना चाहता है तो वे मार्गदर्शन को तैयार हैं। इंदिरा गांधी कृषि विवि रायपुर के प्रोफेसर डॉ. आरयू खान ने कहा कि इंदौर में नया कृषि विवि स्थापित होने से मालवा-निमाड़ क्षेत्र में अनुसंधान को वढ़ावा मिलेगा। संगठन के समन्वयक राधे जाट ने सभी का आभार माना।

प्रार्थना व अन्य गतिविधियां रहेंगी बंद

ग्वालियर, न.सं.

प्रदेश सहित ग्वालियर जिले में 18 दिसंबर, शुक्रवार से कोरोना गाइड-लाइन का पालन करते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी। इस संबंध में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। कक्षाएं संचालित होने के दौरान स्कूलों में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद, स्वीमिंग आदि प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। विद्यार्थी को स्कूल आने पर मास्क लगाना होगा तभी उसे प्रवेश दिया जाएगा। कक्षाओं में एक बेंच पर एक विद्यार्थी को ही बैठाया जाएगा। विद्यार्थियों को स्कूल आने के साथ अपने अभिभावकों का सहमति पत्र भी लाना होगा। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में होनी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर से कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। वहीं कक्षा नौंवी और 11वीं की कक्षाएं नियमित लगाने के संबंध में निर्णय संबंधित स्कूल लेंगे। हालांकि कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी और इनकी कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगी। एक अप्रैल 2021 से नया शिक्षण सत्र शुरू होगा।

फाइल फोटो

इनका कहना है

'कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से नियमित रूप से संचालित होंगी। बच्चों को अभिभावकों का सहमति पत्र लाना होगा। यह सहमति पत्र पूरे सत्र के लिए मान्य होगा। मास्क लगाकर आने पर ही कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।'

विकास जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी

'हमारी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज से बच्चों को नियमित पढ़ाया जाएगा। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाएंगे। स्कूल में लंच लाना वर्जित रहेगा। छात्र केवल घर का पानी साथ ला सकते हैं।'

कौशलेन्द्र सिंह चौहान, अध्यक्ष, निजी स्कूल एसोसिएशन

इन नियमों के तहत संचालित होंगी कक्षाएं

- बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे।
- माता-पिता की सहमति पर विद्यार्थी विद्यालय आ सकेगा। माता-पिता द्वारा दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए होगी।
- कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
- जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यय से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।
- इस दौरान समस्त शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत-प्रतिशत उपस्थित रहेगा।
- छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंध किया जा रहा है तो बसों एवं अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। बसों व अन्य परिवहन वाहनों का एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट के उपयोग से सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधि एसओपी गाइड-लाइन का पालन अनिवार्य होगा।

नौ माह बाद आज से लगेंगी कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं

प्रार्थना व अन्य गतिविधियां रहेंगी बंद

ग्वालियर, न.सं.

प्रदेश सहित ग्वालियर जिले में 18 दिसंबर, शुक्रवार से कोरोना गाइड-लाइन का पालन करते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी। इस संबंध में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। कक्षाएं संचालित होने के दौरान स्कूलों में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद, स्वीमिंग आदि प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। विद्यार्थी को स्कूल आने पर मास्क लगाना होगा तभी उसे प्रवेश दिया जाएगा। कक्षाओं में एक बेंच पर एक विद्यार्थी को ही बैठाया जाएगा। विद्यार्थियों को स्कूल आने के साथ अपने अभिभावकों का सहमति पत्र भी लाना होगा। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में होनी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर से कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। वहीं कक्षा नौंवी और 11वीं की कक्षाएं नियमित लगाने के संबंध में निर्णय संबंधित स्कूल लेंगे। हालांकि कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी और इनकी कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगी। एक अप्रैल 2021 से नया शिक्षण सत्र शुरू होगा।

फाइल फोटो

इनका कहना है

'कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से नियमित रूप से संचालित होंगी। बच्चों को अभिभावकों का सहमति पत्र लाना होगा। यह सहमति पत्र पूरे सत्र के लिए मान्य होगा। मास्क लगाकर आने पर ही कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।'

विकास जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी

'हमारी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज से बच्चों को नियमित पढ़ाया जाएगा। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाएंगे। स्कूल में लंच लाना वर्जित रहेगा। छात्र केवल घर का पानी साथ ला सकते हैं।'

कौशलेन्द्र सिंह चौहान, अध्यक्ष, निजी स्कूल एसोसिएशन

अब तकनीक के प्रोफेसर करेंगे आंदोलन, नहीं मिला सातवां वेतनमान

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रोफेसर और लेक्चरर को सातवां वेतनमान नहीं दिया गया है। प्रोफेसरों द्वारा कई बार धरना-प्रदर्शन करने के बाद भी तकनीकी शिक्षा विभाग अपने प्रोफेसरों को सातवां वेतनमान देने को तैयार नहीं है। विभागीय उदासीनता देख प्रोफेसर अब मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का घेराव करेंगे। इसके बाद भी विभाग नहीं माना तो प्रदेश के प्रमुख चौराहों पर मंत्री के पुतले फूंके जाएंगे।

प्रोफसर्स का कहना है कि प्रदेश का कोई भी विभाग, मंडल, निगम और आयोग ऐसा नहीं है, जहां कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं मिला हो। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आरजीपीवी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और लेक्चरर को पांच साल से सातवां वेतनमान नहीं दिया गया है। वे करीब 15 साल से छठवां वेतनमान लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि एआईसीटीई उन्हें सातवां वेतनमान देने की स्वीकृति तक प्रदान कर चुका है।

यहां तक कि मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ वेतनमान लेने के लिए मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन किसी ने उनके ज्ञापन को तवज्जों नहीं दी हैं। इसके चलते संघ ने विरोध करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते मंत्री सिंधिया का विरोध किया जाएगा। उनके पुतले के चेहरे पर कालिक पोतकर जलाया जाएगा। इस प्रकार का विरोध-प्रदर्शन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक का संचालन करने वाले जिलों के प्रमुख चौराहों पर किया जाएगा। यहां तक कि उच्च शिक्षा विभाग के कई संगठन भी उनके विरोध-प्रदर्शन में पूर्ण सहयोग करेंगे।

मालूम हो कि प्रदेश में 70 पॉलिटेक्निक, सात इंजीनियरिंग कॉलेज और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करीब 1700 प्रोफेसर और लेक्चरर कार्यरत हैं। उन्हें पांच साल पहले लागू किए गए सातवें वेतनमान से वंचित रखा गया है। इन पांच साल में विभाग में दो मंत्री बदले जा चुके हैं और तीसरी मंत्री पदासीन हैं।

छात्रों को देने होंगे कई विकल्प

शिक्षण संस्थानों से संबद्ध बुद्धिजीवियों को 'आलोचनात्मक चिंतन की संस्कृति' का वाहक कहा जाता है। सवाल है कि क्या आज के संदर्भ में भी यह कथन उतना ही सटीक है, जितना वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर से पहले था? यह एक तथ्य है कि आज के दौर में शिक्षक और शिक्षण संस्थानों की भूमिकाओं का विश्लेषण और जरूरी हो गया है।

[illegible]

अच्छी खबर **प्रदेश के 151 कॉलेजों की 55 हजार में से 30 हजार सीट ही भर पाने के कारण लिया निर्णय**

इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आज से एक और मौका

गजेंद्र विश्वकर्मा ● इंदौर

प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की खाली सीटों पर प्रवेश को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत प्रवेश के लिए एक और मौका दे दिया है। प्रदेश के 151 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश में इस वर्ष 55 हजार सीटों में से 30 हजार सीट ही भर पाई है। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेजों की ओर से भी लगातार मांग की जा रही थी कि कोरोना महामारी के कारण बाहर के प्रदेशों में काउंसिलिंग प्रक्रिया लेट शुरू होने का असर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों पर भी पड़ा है। बाहर के कॉलेजों में प्रवेश लेने के

राहत

- **4 दिसंबर तक चली थी काउंसिलिंग इसके बाद प्रवेश बंद कर दिए थे**
- **तकनीकी शिक्षा विभाग से एक और काउंसिलिंग की मिली अनुमति**

इंतजार में विद्यार्थी स्थानीय कॉलेजों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं। इसे लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (डीटीई) ने तकनीकी शिक्षा विभाग से काउंसिलिंग कराने के लिए एक और मौका मांगा था। गुरुवार शाम को इसकी अनुमति दे दी गई है।

सभी चरण होने के बाद पहली बार मिला एक और मौका : डीटीइ की ओर से प्रदेश में प्रवेश कराने के लिए इस

बार काफी समय दिया गया था। पहली और दूसरी काउंसिलिंग होने के बाद तीन चरण में सीधे कॉलेज में जाकर प्रवेश लेने के लिए कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) प्रक्रिया भी कराई गई थी। काउंसिलिंग चार दिसंबर तक चली थी। इसके बाद प्रवेश बंद कर दिए थे। ऐसा पहली बार होगा जब काउंसिलिंग के सभी चरण होने के बाद विद्यार्थियों व कॉलेजों को राहत देते हुए फिर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए डीटीई की वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा। इसके बाद जिस कॉलेज में सीट खाली है वहां प्रवेश मिलेगा। इस बार प्रदेश के ज्यादातर कॉलेजों की कंप्यूटर साइंस (सीएस) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आइटी) ब्रांच की सीटों को छोड़ बाकी ब्रांच में सीट खाली रह गई हैं। इस बार प्रदेश के दो टॉप कॉलेज श्री गोविंदराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (एसजीएसआइटीएस) और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आइईटी) को भी अपनी सीट भरने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी है। सीएलसी चरण में आखिरी दिन सीट भर पाई है।

उर्दू भाषी छात्रों के समर्थन में उतरी जमीअत

भोपाल। मप्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के अंतर्गत मदरसा बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 14 दिसंबर से प्रारंभ ये परीक्षाएं आगामी 30 दिसंबर तक चलेंगी। कक्षा 10वीं परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का समय प्रात: 8 से 11 बजे और कक्षा 12वीं की परीक्षा का समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक निश्चित रहेगा। ऐसे में जमीअत ने एक बार फिर उर्दू टीचर्स की कमी की मांग को उठाते हुए दोहराया है कि वर्ष भर तक उर्दू टीचरों के अभाव में आखिर परीक्षार्थी परीक्षा कैसे दे सकता है। मप्र जमीअत उलमा के प्रेस सचिव मो. इमरान ने कहा कि मप्र शासन से कई बार कमेटी ने शासकीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की मांग की जाती रही है, लेकिन सरकार इस मामले पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से शासकीय स्कूलों में उर्दू के नाम पर क्लास बंक कराई जाती रही है। इस विषय को लेकर छात्रों की स्थिति काफी कमजोर है। ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं में समयानुसार प्रश्त हल करना संभव नहीं है। यह वे छात्र हैं जो उर्दू टीचरों की कमी झेल रहे हैं और छोटी क्लास से अब बड़ी क्लास तक आ गए हैं, लेकिन इनका बेसिक काफी कमजोर हैं। असल में निम्न क्लास के जरिए खानापूर्ति करने वाले स्कूल ऐसे सभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रेस सचिव ने मांग की है कि प्रदेश में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति शासकीय स्कूलों में की जा सकती है। उनकी नियुक्ति से शासकीय स्कूलों के बच्चों को टीचर की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा और उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल हो सकेगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों से मांगा छात्रावासों का रिकार्ड

छात्रों के लौटने से पहले हॉस्टलों को किया जाएगा सेनेटाइज्ड, ऑनलाइन होगा पूरा रिकॉर्ड

सच रिपोर्टर ॥ भोपाल

नए साले में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालीय एवं कॉलेजों को खोलने के आदेश जारी होने के बाद हॉस्टल के साफ-सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्राचार्यों से छात्रावासों की जानकारी मांगी है। कॉलेजों को यह जानकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना है। जानकारी मिलने के बाद विभाग छात्रों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन करेगा, जिसमें छात्रावासों में कुल सीट, छात्र-छात्राओं की संख्या एवं खाली सीटों की जानकारी दी जाएगी। कॉलेज खुलने से पहले सभी हॉस्टलों को सेनेटाईड किया जाएगा। इसके बाद ही छात्र उनमें रुक सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से इस बात का भी पता लग सकेगा कि छात्रावासों में योग्यता अनुसार विद्यार्थियों का आवंटन हुआ है या नहीं। विभाग ने पिछले शिक्षा सत्र में भी कॉलेजों से छात्रावासों ने रहने वाले छात्रों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की भी बात कही थी, लेकिन इस पर काम नहीं हो सका है। अधिकारियों का मानना है कि रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद फर्जी छात्रों के रहने की संभावना कम होगी। छात्रों के ऑनलाइन रिकार्ड दर्ज होने के बाद छात्रावासों का निरीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद भी कोई अव्यवस्था मिलती है तो वार्डन को भी निलंबित किया जा सकता हैं। अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों के छात्रावासों की स्थिति खराब है। छात्रावासों में वर्षों से ऐसे छात्रों ने कब्जा जमा रखा है, जिसकी समय अवधि वर्षों पहले ही खत्म हो चुकी है। अधिकारी बताते हैं कि इन छात्रों के कारण ही हॉस्टल का माहौल खराब हो रहा है। हालांकि अभी कोरोना के कारण सभी हॉस्टल खाली करा दिए गए हैं। सभी छात्र-छात्राएं अपने घर पर ही हैं।

नहीं मिल पाता नए छात्रों को प्रवेश

वर्षों से छात्रावासों में कब्जा जमाए बैठे छात्रों के कारण नए जरूरत मंद छात्रों को हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाती। कहीं छात्रों को प्रवेश मिल भी जाता है, तब तक एक-एक कमरे में चार से छह लोगों को रहना पड़ता है। अब कॉलेज खुलने के बाद कोराना काल में यदि छात्र-छात्राएं वापस आते हैं तो एक कमरे में अधिक छात्र-छात्राओं का साथ रहना खतरना भी हो सकता है।

पीटीएम के साथ हाई स्कूल व हायर सेकंडरी कक्षाओं का आज से नियमित होगा संचालन

स्कूल संचालन के दौरान गाइड लाइन का सख्ती से किया जाएगा पालन

भोपाल, (आरएनएन) । भोपाल जिले सहित प्रदेश में शुक्रवार 18 दिसंबर को संभाग के 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय तो खुलेंगे ही इसी दिन बच्चों के माता पिता संबंधित विद्यालयों में पीटीएम में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण स्कूल परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी।

हालांकि ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई को जारी रखा गया था। अब कोविड संक्रमण के कुछ हद तक नियंत्रित होने पर हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के नियमित संचालन का फैसला लिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने किए दिशा निर्देश जारी

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभ एवं संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड.19 संक्रमण के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुक्रम में यह निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल संचालन के दौरान गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा।

अभिभावकों से होंगी विस्तृत चर्चा

हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के सभी विद्यालयों में 18 दिसंबर को पीटीएम के साथ स्कूल खोले जाएंगे। पीटीएम में कक्षावार अलग-अलग समय पर अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जो अभिभावक नहीं आ सके उनके साथ ऑनलाइन चर्चा करेंगे। अभिभावकों के साथ विद्यार्थी के रिवीजन टेस्ट की कॉपी, प्राप्तांकों एवं आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में चर्चा की जाएगी।

बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसम्बर से स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधा में वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और वाहनों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन विद्यालयों का भ्रमण करके वास्तविक स्थिति का आंकलन कर जानकारी ली जाएगी। विद्यार्थियों, शिक्षकों की उपस्थिति एवं अध्ययन के स्तर की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

20 हजार में फेल से पास कराने का सौदा... वायरल

कमाई का 'खेल' : छात्र नेता की विद्यार्थी से सौदेबाजी का ऑडियो वायरल, अधिकारी और छात्र नेताओं के गठजोड़ की आशंका

लोकेश सोलंकी • इंदौर

शहर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएविवि) में एक छात्र नेता द्वारा विद्यार्थियों से नंबर बढ़वाने के नाम पर सौदेबाजी की जा रही है। अभाविप के प्रकल्प मेडविजन के राष्ट्रीय संयोजक और अभाविप के पूर्व नगर मंत्री वीरेंद्रसिंह सोलंकी की सौदेबाजी करती ऑडियो रिकॉर्डिंग विद्यार्थियों ने वायरल कर दी है। जिनसे छात्र नेता सौदेबाजी कर रहा है, वे एमबीबीएस के विद्यार्थी हैं। छात्रनेता फेल विद्यार्थियों को 10-15 नंबर बढ़ाने की गारंटी तो दे रही रहा है, परिणाम घोषित होने से पहले परिणाम बताने की बात भी छात्रनेता कह रहा है।

देवी अहिल्या विवि। • फाइल फोटो

ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी मैंने सुनी नहीं है। जैसा बताया जा रहा है, यदि वैसा है तो मामला गंभीर है। जांच कर वाई जाएगी। **-प्रो. रेणु जैन, कुलपति**

आवाज मेरी है। सामान्यत: हम कार्यकर्ता व छात्रों के लिए सिफारिश कर देते हैं, लेकिन आर्थिक लेन-देन नहीं किया। मैं ऐसी रिकॉर्डिंग या चर्चा के बारे में नहीं जानता। **-वीरेंद्र सोलंकी, संयोजक मेडविजन अभाविप**

रिकॉर्डिंग में डील... घोषित होने से पहले परिणाम फोन पर

- छात्र नेता सोलंकी एक छात्रा से नंबर बढ़वा कर पास करवाने की डील करता सुनाई दे रहा है। छात्रा उससे पूछती है कि काम हो तो जाएगा? इस पर वह कहता है कि फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहा हूं, पहले भी मैं करता रहा हूं। इसके बाद छात्रा कहती है कि पेमेंट थोड़ा कम नहीं हो सकता। सोलंकी जवाब देता है कि आपके लिए कम ही बता रहा हूं। इधर, काम होने से बच्चे दिसंबर में होने वाली फाइनल ईयर की एग्जाम के योग्य हो जाएंगे। इस पर छात्रा अनुरोध करती है कि पैसे कम हो जाते तो कुछ और विद्यार्थी आ जाते। जिनके दो सब्जेक्ट हैं, उन्हें ज्यादा समस्या है। इस पर अभाविप नेता कहता है कि जिनके दो सब्जेक्ट हैं, उनके लिए हम लोग वन-टू-वन बात कर लेंगे। आगे यह भी जोड़ता है कि जितना अंदर लगना है, उतना तो लगेगा ही। आपके लिए मैंने बता दिया है। उतने में मैं हर किसी का काम नहीं कर सकता। आगे अधिकारी भी कहते हैं। छात्रा कहती है कि 15 आपने बताए, उतने में नहीं होगा। बाद में चर्चा आगे बढ़ती है। सौदा 18 हजार रुपये प्रति विषय पर तय होता है। दावा होता है कि 10 नंबर बढ़ जाएंगे। सोलंकी आश्वस्त कर देता है कि परिणाम घोषित होने से पहले नंबर बता देगा।

छतरपुरः लंबे समय से गायब छह शिक्षकों को किया बर्खास्त

छतरपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमर बहादुर सिंह ने जिले के विभिन्न विद्यालयों में लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे 6 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए है। ये सभी शिक्षक कई बार सूचना देने के बाद भी अपने विद्यालयों में उपस्थित नहीं हुए थे। जिला शिक्षा अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि नीतू खरे और रचना भार्गव गत 13 वर्षों से अनुपस्थित चल रहीं थीं। सीमा दोहरे 9 वर्ष से, प्रजेश प्रताप सिंह अहिरवार तथा कीर्ति सक्सेना संविदा शिक्षक श्रेणी 3 शासकीय प्राथमिक शाला मुंगवारी 6-6 वर्ष से अनुपस्थित थे। श्रीमती विनीता जैन संविदा शिक्षक श्रेणी 3 शासकीय प्राथमिक शाला श्यामाझोर गत 4 वर्ष से अपनी शाला से अनुपस्थित थी।

एक जगह एकत्रित नहीं होंगे छात्र

विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्यों को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि विद्यालय संचालन के समय छात्र एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। विद्यालय में प्रार्थना सामूहिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। छात्रों की पठन-पाठन व्यवस्था के लिए चल रहे ऑनलाइन कार्यक्रम जारी रहेंगे। बताया गया कि शैक्षणिक सत्र समाप्ति की ओर है इस समयावधि में पठन-पाठन व्यवस्थित तरीके से हो इसलिए स्कूलों की सघन मॉनीटरिंग में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस समयावधि में अगर कोई शिक्षक लापरवाही करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

5 विद्यालयों का करना है निरीक्षण

जिला स्तर के सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित मॉनीटरिंग अमले को प्रतिदिन 5 स्कूलों से वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण कर विद्यार्थियों में शिक्षकों से फीडबैक लिया जाएगा। जिसका वीडियो स्क्रीनशॉट विमर्श पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सप्ताह में कम से कम एक दिन विद्यालयों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करेंगे।

केआईआईटी को क्यूसीआई-डीएल शाह क्वालिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

नई दिल्ली स्व.स.से.

केआईआईटी डीम्ड विश्वविद्यालय को तीसरे वर्चुअल क्वालिटी कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में गुरुवार को 13वीं क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया - डी.एल. शाह क्वालिटी रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केआईआईटी विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार मानक संचालन प्रक्रिया (एसएपी) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दिया गया है, जिसे वहां की प्रो-वाइस चांसलर, प्रो. सस्मिता सामंता ने ग्रहण किया। केआईआईटी के अतिरिक्त सीएमसी वेल्लोर, केजी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर और चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब एवं शैक्षणिक संस्थानों को पुरस्कार सूची में शामिल किया गया। इस उपलब्धि पर केआईआईटी एवं केआईएसएस के संस्थापक, डॉ. अच्युत सामंत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल नवाचार और सर्वोत्तम आचरण को अपनाने की आवश्यकता है और उन्होंने इस पर जोर भी दिया है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए डीएल शाह ट्रस्ट को धन्यवाद दिया।

शासकीय कन्या महाविद्यालय में हुआ वेबिनार का आयोजन

भास्कर न्यूज | सतना

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र विभाग में गुरुवार को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के माध्यम से डॉ.अर्पिता नेमा अत्रेवाल, चिकित्सक गर्भ संस्कार विशेषज्ञ एवं योग गुरु ने छात्राओं को मासिक चक्र में होने वाली अनियमितताओं में आयुर्वेद,योग व ध्यान द्वारा उपचार पर छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा इन अनियमितताओं का कारण,तनाव, थकान, वजन घटना या बढऩा, पीसीओ एसपीआईडी अत्याधिक कैफीन का सेवन बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यात्म के अनुसार मनुष्य एक आत्मा है, जिसमें मन बुद्धि संस्कार शामिल है। जैसे एक मोटर चालक मोटर को नियंत्रित करता है, वैसे ही आत्मा हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। अतः इसके उपचार हेतु गुडहल, नीम, सुपारी की पत्ती, हरसिंगार, अमरुद की पत्ती, इमली की पत्ती, अंजीर इत्यादि लाभदायक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.नीलम रिछारिया ने की। उन्होंने इस विषय को समसामयिक बताते हुए छात्राओं को डॉ. अर्पिता की बातों पर ध्यान देने व उसे अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में डॉ.शोभा गुप्ता, डॉ.अर्पिता नेमा अत्रेवाल, डॉ.शुचिता तिवारी, डॉ. राजनिधि सिंह, डॉ.आभा खरे, डॉ.अनूप सिंह बघेल, हसीन अहमद, अमित निराला, लबी सिंह, ममता श्रीवास्तव, बबिता आदि उपस्थित रही।

गर्ल्स कॉलेज के विकास के लिए 2 करोड़ का प्रोजेक्ट

भास्कर न्यूज | सतना

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले के इकलौते शासकीय कन्या स्वशासी महाविद्यालय को विकास किए जाने की सूची में शामिल किया गया है। इसके लिए दो करोड़ की लागत से तैयार किया गया प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर कंस्ट्रक्शन कार्य करीब डेढ़ करोड़ की लागत से होना है जबकि शेष राशि से महाविद्यालय में अतिरिक्त कमरों के साथ अन्य जरूरी कार्य कराए जाएंगे। बताया जाता है कि निर्माण कार्य के बाद महाविद्यालय की छात्राओं को सभी सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी।

ये होंगे निर्माण

महाविद्यालय में चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत सेमिनार हॉल बनाया जाएगा जो सर्व सुविधा युक्त होगा। इसके अलावा दो कमरे और महाविद्यालय की रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा।

स्टेशन रोड की तोड़ी गई बाउंड्री

आज का गर्ल्स कॉलेज कभी डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता था। आवश्यकता के मद्देनजर यह महाविद्यालय एक तरह से जिले की छात्राओं के नाम उच्च शिक्षा के लिए दे दिया गया किन्तु राजा-रजवाड़ों के जमाने में बनी बाउंड्री जर्जर होने की वजह से यहां कई तरह की घटनाएं होने की आशंका बनी हुई थी, लिहाजा भवन निर्माण शुरू करने के पहले बाउंड्री की मरम्मत को प्राथमिकता से लिया गया है। निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक आगामी शैक्षणिक सत्र में तैयार किया गया प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया जाएगा।

एसएमसी और छात्रावास की ऑडिट करने पहुंची चार सदस्यीय टीम

भास्कर न्यूज | सतना

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिले के विद्यालयों में गठित शाला प्रबंध समिति (एसएमसी) और सर्वशिक्षा अभियान के सभी छात्रावासों की ऑडिट करने के लिए चार सदस्यीय टीम सतना भेजी है। गुरुवार को भोपाल से आई टीम द्वारा सोहावल और नागौद विकासखंड के एसएमसी एवं छात्रावासों की ऑडिट की गई। प्रतिदिन दो विकासखंडों की ऑडिट की जाएगी। सभी स्कूलों की एसएमसी और छात्रावासों के रिकार्ड जिला शिक्षा केन्द्र में बुलाए गए हैं।

अभी बंद रहेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि (आरजीपीवी) से संबद्ध कॉलेज 1 जनवरी से नहीं खुलेंगे। कॉलेज खोलने की तारीख पर शासन स्तर पर निर्णय होगा। पिछले दिनों सिर्फ उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेज को 1 जनवरी से खोलने का निर्णय हुआ है। उधर, तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार आरजीपीवी द्वारा इंजीनियरिंग समेत सभी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार संचालित किए जाते हैं। इसलिए पहले सेमेस्टर जनवरी में परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसके बाद ही कॉलेज खुल सकेंगे। तकनीकी शिक्षा आयुक्त पी. नरहरि का कहना है कि 1 जनवरी से कॉलेज खोलने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों पर लागू होगा। आरजीपीवी से संबद्ध कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की 1 जनवरी से परीक्षा प्रस्तावित हैं। परीक्षा ऑनलाइन मोड पर ही होना है, इसलिए परीक्षा के बाद ही कॉलेज खुलेंगे।

अंततः सहायक शिक्षक सस्पेंड

विभागीय जांच शुरू • एसडीएम नागौद करेंगे परीक्षण, एक माह के अंदर कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट

भास्कर न्यूज | सतना

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने प्राथमिक शाला शिवरामपुर के सहायक शिक्षक उद्धराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित सहायक शिक्षक को बीईओ कार्यालय अमरपाटन से अटैच किया गया है। कलेक्टर ने मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी उचेहरा के एसडीएम दिव्यांक सिंह को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट 30 दिन के अंदर तलब की गई है। उचेहरा के प्रभारी तहसीलदार अजय राज सिंह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

क्या हैं आरोप

आरोप हैं कि उचेहरा थाना अंतर्गत बांधी मौहार में एमपीपीटीसीएल की 132 केवी पावर लाइन बिछाने के दौरान राजस्व विभाग के भृत्य रामनाथ वर्मा के साथ 2 ठेका श्रमिकों की पिटाई और मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार शैलेन्द्र बिहारी शर्मा, ईई सौरभ तिवारी और एई एसके पाठक पर हमले की कोशिश की वारदात के पीछे प्राथमिक शाला शिवरामपुर के सहायक शिक्षक उद्धराज सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश कनिष्ठ एवं राजस्व अधिकारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल में एसडीएम दिव्यांक सिंह, एसडीएम सिटी राजेश शाही, रघुराजनगर के एसडीएम पीएस त्रिपाठी, रामपुर बाघेलान की एसडीएम संस्कृति शर्मा, डिप्टी कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, तहसीलदार बीके मिश्रा, नायब तहसीलदार सविता यादव, अजयराज सिंह और नायब तहसीलदार आशुतोष मिश्रा भी शामिल थे।

बोलेरो जब्त, फरार हैं आरोपी

वारदात में शामिल आरोपी नीलू जायसवाल, अशोक जायसवाल और राजेन्द्र सिंह (सभी निवासी बांधी मौहार) फिलहाल फरार हैं। इनके खिलाफ उचेहरा थाने में आईपीसी की धारा- 353, 332, 394, 506, 34 के अलावा अजा एवं अजजा अधिनियम की धारा- 3(1) (द) एवं अजा एवं अजजा अधिनियम की धारा- 3(1) (ध) के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त बोलेरो नंबर एमपी 19 सीसी 1657 जब्त कर ली गई है। यह गाड़ी शैलेन्द्र सिंह जायसवाल पिता तिलकधारी निवासी हिरौंदी (मझगवां) के नाम पर रजिस्टर्ड है।

अभियंता संघ ने मांगी सुरक्षा की गारंटी

इसी बीच एमपीपीटीसीएल की 132 केवी पावर लाइन बिछाने के दौरान दबंगों की हिंसक वारदात से नाराज मध्यप्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के नाम एसडीएम सिटी राजेश शाही को सौंपे ज्ञापन में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नहीं दिए जाने पर अभियंता संघ ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी है। प्रतिनिधि मंडल में अधीक्षण यंत्री एसपी शर्मा, आरबी बंसल, कार्यपालन यंत्री पीसी निगम, एमपी पटेल, अभय सक्सेना, जय श्रीवास्तव, सौरभ तिवारी, सहायक यंत्री दिनेश मोरे, रवि प्रकाश पांडेय, शैलेन्द्र अवस्थी और एसके पाठक शामिल थे।

कल स्कूल खुलने के साथ ही सरकारी स्कूलों में होगी पैरेंट्स-टीचर मीटिंग

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल । कोरोना कहर के कारण पिछले छह माह से बंद सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल कल से खुलेंगे। सरकारी स्कूलों में पहले दिन पैरेंट्स-टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षावार अलग-अलग समय पर अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जो अभिभावक नहीं आ सकेंगे, उनसे ऑनलाइन चर्चा की जाएगी। अभिभावकों के साथ विद्यार्थी को रिवीजन टेस्ट की कॉपी दिखाई जाएगी। इस दौरान अभिभावकों से छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। मालूम हो कि निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी कक्षाएं पूरे समय के लिए नियमित रूप से लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना गाइड लाइन के पालन (भीड़ प्रबंधन) की जिम्मेदारी स्कूलों पर छोड़ी है। स्कूल प्रबंधन को एक बार में सीमित संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बुलाना होगा। भले ही इसके लिए स्कूलों को दो-तीन शिफ्ट में कक्षाएं लगानी पड़ें। हालांकि विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसा करने से पहले स्कूल प्रबंधन को बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति लेना होगी, जो पूरे सत्र (2020-21) के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान रूप से लागू रहेगी।

विधायक मां को 10वीं पास करवाने के लिए बेटी बन गई 'गुरु'

स्कूल में परीक्षा देती विधायक रामबाई परिहार। ●नईदुनिया

जबलपुर/दमोह (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पथरिया (दमोह) विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों कुछ अनूठा हो रहा है। यहां की विधायक रामबाई परिहार इन दिनों अपनी ही बेटी मेघा की शिष्य बनकर पढ़ाई कर रही हैं। वे राज्य ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा दे रही हैं, इसलिए बेटी उन्हें पढ़ा रही हैं। विधायक का कहना है कि 'मैं पढ़कर और आगे बढ़ना चाहती हूं और मेरी बेटी इसमें मदद कर रही है'।

रामबाई के बसपा से विधायक चुने जाने के बाद से बेटी मेघा को लगता था कि मां को और अधिक पढ़ा-लिखा होना चाहिए, ताकि वे राजनीति और नेतृत्व की दुनिया में और आगे जा सकें। विधायक मां ने भी बेटी की इस स्वेच्छा को सम्मान दिया और राज्य ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा देने का मन बनाया। प्रश्न खड़ा हुआ कि कोरोना काल में पढ़ाएगा कौन? यह समस्या उनकी बेटी ने हल करते हुए मां को परीक्षा की तैयारी करवाना शुरू कर दी।

मिसाल

- **पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई को पढ़ा रही उनकी बिटिया**
- **बेटी चाहती है कि राजनीति में सफल हो रही मां शिक्षा में भी हो सफल**

अब बेटी की सहायता से विधायक मां लगभग में आठ से 10 घंटे पढ़ाई कर रही हैं। उनका परीक्षा केंद्र जेपीवी कन्या स्कूल है। बेटी मेघा खुद भी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तैयारी कर रही है।

सुबह पांच बजे उठा देती है बेटी

आमूमन घरों में माताएं अपने बच्चों की पढ़ाई का शेड्यूल बनाती हैं, लेकिन इस मामले में बेटी ने विधायक मां के अध्ययन का टाइम टेबल तय किया है। बेटी देर रात तक मां को पढ़ती है और सुबह पांच बजे फिर उठा देती है। वही मां को चाय बनाकर देती है ताकि उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही रहे। इस बीच बेटी स्वयं की यूपीएससी संबंधी पढ़ाई के लिए भी समय निकालती है।

मेरी बेटी ने मुझमें शिक्षा के प्रति फिर अलख जगाई। वह चाहती है कि मैं पहले 10वीं पास करूं, फिर और आगे पढ़ाई करूं। बेहतर शिक्षा के साथ डिग्री भी जरूरी है, इसलिए मैं भी पूरे मन से परीक्षा के लिए जुटी हूं। शिक्षा के प्रति बेटी की लगन को ही मैंने अब अपनी लगन बना लिया है।

- रामबाई परिहार, विधायक, पथरिया विधानसभा, दमोह, मध्य प्रदेश

8 सदस्यीय समिति ने सौंपी शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट

IIT में लागू नहीं होगा रिजर्वेशन!

नई दिल्ली, एजेंसी। आईआईटी में स्टूडेंट्स के एडमिशन और फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्यीय समिति ने सिफारिश की है कि 23 इंजीनियरिंग स्कूलों को सीईआई (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत आरक्षण से छूट दी जानी चाहिए, और विशिष्ट कोटा की बजाए आउटरीच अभियानों और फैकल्टी रिक्रूटमेंट के माध्यम से विविधता के मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए। समिति की अध्यक्षता आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी. रामगोपाल राव ने की थी। रिपोर्ट में कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित और मान्यता प्राप्त होने के नाते आईआईटी को आरक्षण से छूट के लिए सीईई अधिनियम 2019 के तहत (क्लॉज-4) सूचीबद्ध होना चाहिए। इन संस्थानों के कर्तव्यों और उनकी एक्टिविटी के नेचर को ध्यान में रखते हुए लिस्ट में आईआईटी को शामिल करने के लिए इस पर तुरंत पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

AMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे मोदी, 1965 के बाद जाने वाले पहले PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के 100 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। संस्थान की ओर से जारी बयान के मुताबिक 22 दिसंबर को इस समारोह में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी भाग लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, आखिरी बार साल 1964 में किसी पीएम ने यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जब लाल बहादुर शास्त्री ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया था। एएमयू के कुलपति, प्रोफेसर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समारोह में सभी लोग राजनीति से ऊपर उठकर शामिल हों।

29 जिलों के पांच हजार विद्यार्थी बने सरकारी खजाने पर बोझ

विकास कुमार जैन, भोपाल। मप्र सरकार राज्य के 51 कॉलेज समाप्त करने जा रही है। उक्त कॉलेजों में 100 से कम प्रवेशित विद्यार्थी, प्रोफेसर और स्टाफ को युक्तियुक्तकरण कर दूसरे कॉलेज में विलय किया जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था गत वर्ष तत्कालीन उच्च शिक्षामंत्री जीतू पटवारी कर गए थे। 51 कॉलेजों पर प्रवेशित करीब पांच हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने में सरकारी खजाने बोझ बढ़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली सरकार के निर्णय को यथावत रखने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 497 सरकारी कॉलेजों के वर्तमान सत्र 2020-21 में यूजी-पीजी में चार लाख प्रवेश हुए हैं। इसके बाद भी सूबे के 51 कॉलेजों में 100 से कम प्रवेश हुए हैं। ऐसे कॉलेजों को समाप्त कर उनमें प्रवेशित करीब 5000 विद्यार्थियों को नजदीक के बड़े कॉलेज या दो छोटे-छोटे कॉलेज का युक्तियुक्तकरण एक किया जाएगा। इससे राज्य के 51 कॉलेजों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

उक्त कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर सहित अन्य स्टाफ को दूसरे कॉलेजों के रिक्त पदों के तहत पदस्थ किया जाएगा। प्रदेश में करीब आधा दर्जन कॉलेज ऐसे हैं, जिनमें दो दर्जन विद्यार्थी भी नहीं हैं। जबकि प्रोफेसर और कर्मचारियों को लाखों रुपए का वेतन प्रतिमाह दिया जा रहा है। उक्त कॉलेजों में स्वयं का भवन के अलावा बिजली, पानी और संसाधनों का काफी अभाव है।

प्रदेश टुडे एजुकेशन

12 साल में बढ़े 314 कॉलेज

मध्यप्रदेश में 2008 में 302 सरकारी कॉलेज थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय नेता और मंत्री की मांगों पर दस साल 214 नए कॉलेजों खोल दिए। इससे उनकी संख्या अब 516 तक पहुंच गई है। इसमें करीब 51 कॉलेज सरकारी खजाने पर बोझ बन गए हैं, जिन्हें अब समाप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है।

फर्जीवाड़ा भी होगा खत्म: उक्त कॉलेजों में विद्यार्थी सिर्फ नाम के लिए प्रवेश लेकर सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। यहां से स्कॉलरशिप तक लेते हैं। कुछ कॉलेजों में सिर्फ अतिथि विद्वान प्राचार्य की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। क्योंकि वहां कोई प्रोफेसर नहीं है।

51 कॉलेज होंगे समाप्त

सतना चार, उज्जैन और डिंडौरी में तीन-तीन, सिंगरौली, शिवपुरी और सीधी में तीन-तीन, अनूपपुर, सीहोर, शहडोल, हरदा, मंडला, रायसेन, धार, श्योपुर, बड़वानी और बुरहानपुर में दो-दो, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, ग्वालियर, होशंगाबाद, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नीमच, सागर, पन्ना, रतलाम और रीवा में एक-एक कॉलेज।

छात्रावास खोलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र

भास्कर न्यूज | वाराणसी

विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ साइंस के शोधछात्रों के लिए छात्रावास खुले हैं। लेकिन अन्य छात्रावासों में यूजी और पीजी के छात्रों को रहने देने की बात से आक्रोशित रुइया छात्रावास के संस्कृत ब्लॉक के यूजी और पीजी के छात्र हॉस्टल के सामने सड़क जामकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों की मांग है की अन्य छात्रावासों की तरह रुइया संस्कृत ब्लॉक में भी यूजी और पीजी के छात्रों को रहने की अनुमति दी जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बैरियर लगाकर रास्ता बंद कर दिया। इस दौरान छात्रों ने वीसी का रोना है बाबू लोग कोरोना हैं,

हास्टल वार्डन मुर्दाबाद, चीफ प्राक्टर हास्टल खोलो आदि के पोस्टर लिखकर प्रदर्शन करते हुए हास्टल खोलने की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों के बीच सुरक्षा कारणों से हास्टल खोलने से मना कर दिया है।

वित्तीय अनुशासन और कार्य कुशलता से काम करें प्राचार्य

शहडोल. प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्किट हाउस शहडोल में संभाग के महाविद्यालयों के प्राचार्यो की बैठक लेकर संभाग में संचालित महाविद्यालयों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने ऐसे महाविद्यालय भवन जो बनकर तैयार है तथा जिन महाविद्यालयों के भवनो का भूमि भूजन होना है, उनके संबंध में अलग-अलग पूंछताछ की। बताया गया कि 100 छात्र से कम वाले अनूपपुर जिले के बेंकटनगर एवं शहडोल मुख्यालय का संस्कृज कॉलेज है। बैठक में डिपोटेशन पर जाने वाले प्राध्यापको तथा ऐसे प्राध्यापक व सह प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक जिनके प्रमोशन होने है उनकी भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्राचार्यगण उनके कॉलेजो में नवीन कोर्स खोलने वाले विषयों के संबंध में होमवर्क कर जानकारी बताएं।

एन. रघुरामन, मैनेजमेंट गुरु [raghu@dbcorp.in]

बच्चों के ध्यान के लिए 'ई-क्लास' में लें 'शुगर क्लास'

वह पांचवीं कक्षा में है और महज 11 साल की है, पुणे में रहती है। चूंकि कोविड के कारण स्कूल में कक्षाएं नहीं लग रही थीं, इसलिए वह माता-पिता के साथ महाराष्ट्र के भिवंडी में भोकारी गांव स्थित उनके गन्नों के खेत चली गई। उसने जब 14 एकड़ में फैले खेत में प्रवासी कामगार माता-पिताओं के साथ घूमते बच्चों के साथ काम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वे आधारभूत स्कूली शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उनका परिवार आजीविका के लिए घूमता रहता है।

मिलिए दिविजा दारेकर से, जिसने अपनी अच्छी दोस्त, नौंवी कक्षा में पढ़ने वाली, पुणे की ही 14 वर्षीय सेजल पवार के साथ आधारभूत कक्षाएं लेना शुरू किया है, जहां वे बच्चों को अल्फाबेट, नंबर और क्राफ्ट पढ़ाती हैं। अपने कई पाठों में, इन दोनों ने हर छात्र से खुद का परिचय देने कहा और उनका पसंदीदा पेशा पूछा, जिसके वे सपने देखते हैं। कोई छात्र पुलिसवाला बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर। यानी उनके सपने हैं, पर वे दिशाहीन हैं। दिविजा और सेजल ने उन्हें दिशा देने के लिए सामाजिक कार्य का फैसला लिया और कक्षा का नाम 'शकर शाला' बिल्कुल उपयुक्त रखा। दिलचस्प यह है कि इस 'शुगर क्लास' के छात्र यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें रोज पढ़ाया जाए।

मेरे हिसाब से यह कक्षा मार्केटिंग के दृष्टिकोण से तैयार नहीं की गई, बल्कि यह इसलिए मशहूर हुई क्योंकि इन दो स्कूली बच्चियों ने प्रवासी मजदूरों को ऐसे हैरान करने वाले तथ्य और आंकड़े बताए, जिनके बारे में ये बच्चे जागरूक नहीं थे। कुलमिलाकर अनजान क्षेत्र की शक्कर में डूबी जानकारी के साथ सैद्धांतिक पाठ से कमाल हो सकता है।

इस सोमवार और मंगलवार को मेरी मध्य प्रदेश के कई शिक्षकों के साथ मीटिंग की शृंखला थी और सभी का सवाल था कि ई-क्लास में बच्चों का ध्यान कैसे लगाएं, जहां छात्र न सिर्फ अपना कैमरा, बल्कि अपना दिमाग भी बंद कर लेते हैं और उनकी उपस्थिति की निगरानी करना भी मुश्किल है। अगर आप उन शिक्षकों और माता-पिताओं में से एक हैं, जिन्होंने बहुत से बच्चों को क्लास के दौरान हर तरह से 'स्विच ऑफ' करते देखा है, तो समय आ गया है कि हम पढ़ाने और पैरेंटिंग की बेहद अनुशासन वाली शैली छोड़ दें। कोविड के हमले के बाद, 'डिजिटली निर्भर' बच्चे चाहते हैं कि हम उन्हें चौंकाएं।

जब भी मैं ई-क्लास में एमबीए छात्रों से पहली बार बात करता हूं तो एक क्विज प्रोग्राम खेलता हूं, 'कौन बनाएगा दिमाग का दही'। इसमें सिर्फ पांच सवाल होते हैं और दो मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। हर जवाब झट से देना होता है। मेरा पहला सवाल है, 'दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन-सा है?' स्वाभाविक है कि मुझे तुरंत चीन जवाब मिल जाता है। जब मैं तुरंत पूछता हूं कि दूसरा कौन है, छात्र तुरंत चीखते हैं, 'भारत'। लेकिन जब मैं तीसरा देश पूछता हूं तो 98% छात्र चुप हो जाते हैं और वे अमेरिका नहीं कह पाते। उसके बाद सभी जवाब गलत होंगे और मैं तेजी से पूछता रहूंगा और जवाब भी देता रहूंगा ताकि उन्हें गूगल करने का मौका न मिले। फिर मैं सबसे ज्यादा आबादी वाले शीर्ष 10 देश उनकी प्रतिशत में हिस्सेदारी के साथ साझा करता है। जैसे चीन का 19.4%, भारत 17.5% और अमेरिका 4.5%। फिर मैं उन्हें बताता हूं कि अगर वे मेरी कक्षा में ध्यान देंगे तो उनकी हर क्षेत्र में गहरी जानकारी बढ़ेगी।

फंडा यह है कि, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का 'ई-क्लास' में एक घंटे तक ध्यान न भटके, तो शुरुआत के 5-7 मिनट 'शुगर क्लास' पर खर्च करें।

पोस्टर मेकिंग | छात्रों ने दिखाया टैलेंट

सिटी रिपोर्टर . सतना

कोविड 19 के इस कठिन समय पर भी सीबीएसई बोर्ड से संबंद्ध ब्लूम्स एकेडमी में शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से छात्र-छात्राओं को जोड़े रखा है। इसी प्रक्रिया में जूनियर ग्रुप के कक्षा 6,7 एवं 8 के छात्र-छात्राओं ने कोविड 19 की समस्या पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। जिसमें सभी प्रतिभागियों ने चित्रकारी के माध्यम से विभिन्न रुप में इस समस्या के बारे में अपने विचार पोस्टर में व्यक्त किए। जिसमें अक्षत कुमार द्विवेदी, मानसी यादव व प्रिसी मिश्रा ने प्रथम स्थान अर्जित किया। द्वितीय स्थान पर वेदिका सिंह व स्नेहा उमर्लिया रहे, तृतीय स्थान पर अंजली व कीर्ति तिवारी रहे। विद्यालय चेयरपर्सन मधु अग्रवाल ने सभी स्टूडेंट्स को स्मृति चिन्ह प्रदान किया तथा इस कोविड 19 की समस्या से बचने एवं क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य जीसी बेहरा ने सभी छात्र-छात्राओं एवं आए अभिभावकों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

शिक्षक संघ की बैठक आयोजित

निप्र | जवा

जवा तहसील के अध्यापक संवर्ग से राज्य स्कूल शिक्षा सेवा अंतर्गत नियुक्त हुए प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक जिनकी सेवाएं 12 वर्ष पूर्ण हो गई है।

उनके प्रथम क्रमोन्नति की फाइल डीईओ कार्यालय में लटक गई है। उक्त संबंध में आजाद अध्यपक संघ की बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में 1 अगस्त 2018 को या पश्चात 12 वर्ष पूर्ण कर चुके प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक जिन्हें प्रथम क्रमोन्नति के लाभ मिलना था कि फाइल पेन्डिंग रखी गई है। उक्त संबंध में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा 2018 अन्तर्गत जारी आदेश में प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक के नियोक्ता सक्षम अधिकारी कौन होगा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। जिसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के पत्र दिनांक 22 जून 20 के तहत आयुक्त लोक शिक्षण से मार्गदर्शन चाहा गया है। मार्गदर्शन के अभाव में सैकड़ों प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति हेतु कतार में खड़े हैं। अध्यापक संवर्ग प्राथमिक शिक्षक संवर्ग का छठवे वेतन एरियर्स की तीसरी किस्त, लोकायुक्त प्रकरण में लंवित पांच सैकड़ा शिक्षकों का राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन, सातवे वेतनमान की शेष 12,14 माह की अंतर राशि का भुगतान, जिला के नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन सहित कई समस्याएं हैं। जिनका आज तक निराकरण नहीं हो सका है। जिससे नवीन शिक्षक संवर्ग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।बैठक में मुख्य रूप से प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह, बालेन्द्र शेषर द्विवेदी, संजय सिंह, मनीष चंदानन, लोली तिवारी, पुष्पेंद्र द्विवेदी, दयानंद द्विवेदी रामचंद्र पाण्डेय, ओमप्रकाश मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

आज का इतिहास

- **1271** : मंगोल सम्राट कुबलई खान ने अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा। इसके साथ ही युआन वंश की शुरुआत हुई।
- **1777** : अमेरिका में पहली बार नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाया गया।
- **1799** : अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन के पार्थिव शरीर को माउंट वर्नान में दफनाया गया।
- **1839** : अमेरिका के जॉन ड्रेपर ने पहली बार किसी आकाशीय पिंड (चंद्रमा) की तस्वीर उतारी।
- **1849** : विलियम बांड ने टेलीस्कोप के जरिये चांद की पहली फोटोग्राफ ली।
- **1865** : अमेरिका में पहला मवेशी आयात कानून पारित हुआ।
- **1878** : तत्कालीन सोवियत संघ को महाशक्ति में बदलने वाले नेता जोसेफ स्टालिन का जन्म।

आज का इतिहास

1756 गुरु घासीदास - भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की संत परंपरा में सर्वोपरि माने जाने वाले संत का जन्म हुआ।

1887 भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार का जन्म हुआ।

1980 मुकुट बिहारी लाल भार्गव - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक सभा के सदस्य का निधन हुआ।

1960 नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ।

1997 भारत और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि सम्पन्न।

1999 श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा पर हुए जानलेवा हमले में 25 लोगों की मृत्यु तथा 100 घायल।